बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 22

निर्भरता का प्रश्न

ईंधन के आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। देश में कच्चे तेल का 80 फीसदी आयात किया जाता है और यह आयात मुख्यतया इराक, सऊदी अरब और प्रतिबंधों से जूझ रहे ईरान से किया जाता है। कुल मिलाकर ईंधन क्षेत्र में देश की आयात निर्भरता सन 2000 के 21 फीसदी से बढ़कर 2015 में 36 फीसदी तक पहुंच गई। अगर देश में ईंधन का उत्पादन अतीत की तुलना में तेज गति से बढ़ा तो भी सन 2040 तक यह 50 फीसदी हो जाएगा। यह एक बड़ी समस्या है जो निरंतर चली आ रही है और इसका कोई आसान हल नजर नहीं आ रहा है। जैसे-जैसे देश की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण होता जाएगा वह ऊर्जा के पुराने कम घने स्वरूपों मसलन बायोमास आदि से अधिक घनत्व वाले स्वरूपों की ओर बढ़ती जाएगी। हमारे देश में तेल, गैस और गुणवत्तापूर्ण कोयला जैसे ईंधन के स्रोत उस पैमाने पर नहीं हैं जितनी कि आवश्यकता थी। बहरहाल, इस निरंतर निर्भरता का बाह्य खाते के संतुलन और समग्र वृहद आर्थिक स्थिरता पर जो असर हो रहा है वह कतई बेहतर नहीं है। उदाहरण के लिए तेल कीमतों में बढ़ोतरी घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, राजकोषीय घाटे पर दबाव डालती है और भुगतान संतुलन के संदर्भ में संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। सन 1991 में ऐसा हो चुका है और 2013 में भी हम करीब-करीब उसी स्थिति में पहुंच गए थे।

विकल्प क्या हैं? यह सच है कि हमारे देश में कोयले का प्रचुर भंडार है परंतु उसका काफी हिस्सा अच्छी गुणवत्ता का नहीं है। भारतीय कोयले को अच्छी तरह ज्वलनशील बनाने के लिए उसे प्रसंस्कृत करने की आवश्यकता होगी। यह प्रसंस्करण कोयले की धुलाई से होता है और इसके लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इससे कोयला संयंत्र के आसपास जल संकट हो सकता है।

महाराष्ट्र के विदर्भ जैसे इलाके जो पहले ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं वहां ऐसे नए कोयला संयंत्र नहीं लगाए जा सकते। इन संयंत्रों के उत्सर्जन का ग्रीनहाउस गैसों पर तो असर पड़ता ही है, इसके अलावा भी ये आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। इस तरह देखें तो कोयला तो कोई विकल्प है ही नहीं। उदाहरण के लिए ग्लेनकोर ने कोयला उत्पादन सीमित करने का वादा किया है। ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प हैं? हम भविष्य में कई वर्षों तक कोयले पर निर्भर रह सकते हैं लेकिन यह स्पष्ट है कि हमें इसका विकल्प तलाश करना होगा। कोयले से गैस बनाना एक विकल्प हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी एक उम्मीद हैं। खासतौर पर इसलिए क्योंकि फिलहाल वे लागत के मामले में व्यवहार्य हैं। बहरहाल, सौर और पवन ऊर्जा मौजूदा स्रोतों का उचित विकल्प नहीं हैं क्योंकि उनका उत्पादन अलग-अलग होता है। पवन चक्की से बिजली तभी बनती है जब हवा चल रही हो और सौर ऊर्जा के लिए सूरज का चमकना आवश्यक है। हमें इस बारे में नीतिगत तरीके से विचार करना होगा। उसे दो बातों पर विचार करना चाहिए: पहली बात संकट के समय बचाव का उपाय और दूसरा वृहद अस्थिरता को दूर करना। इसके लिए उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद हो। यूएई और सऊदी अरब के साथ इस दिशा में किया जा रहा सहयोग स्वागतयोग्य है। दूसरा, व्यापार संतुलन को बेहतर बनाने का कोई विकल्प नहीं है। हम आयात पर निर्भर रह सकते हैं लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा निर्यात अधिक हो और स्थिरता बरकरार रहे। वृहद आर्थिक स्थिरता का केवल यही एक रास्ता है।

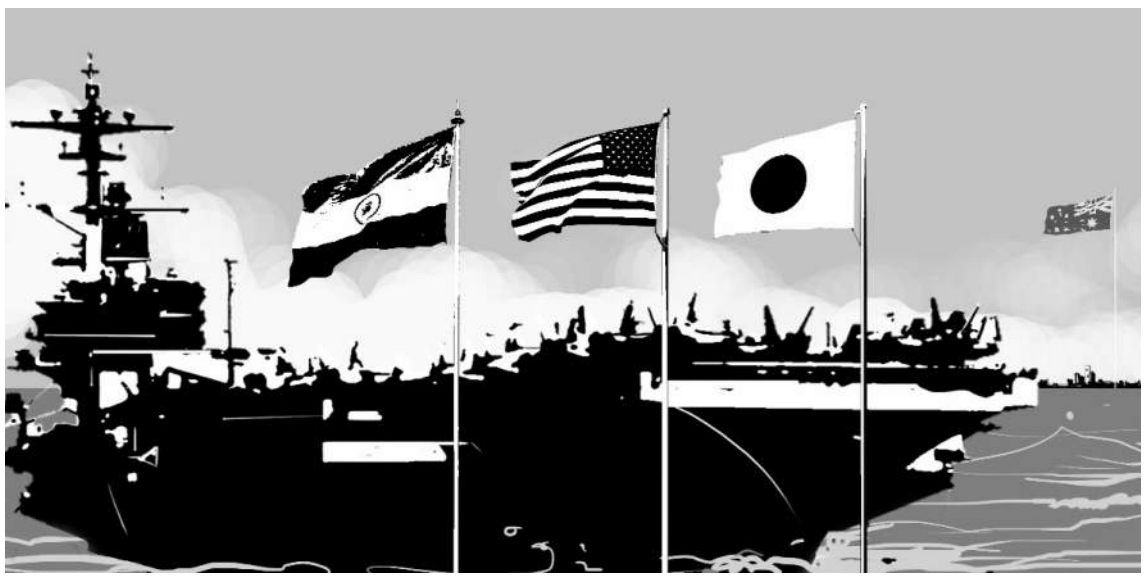

अजय मोहंती

भारत के लिए क्वाड गुट अभी खास उपयोगी नहीं

सामरिक जरूरत के तौर पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक गुट बनाना ऐसा विचार है जिसका वक्त आना बाकी है। विश्लेषण कर रहे हैं **प्रेमवीर दास**

हाल में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक गुट बनाने का मसला सामरिक जगत में काफी चर्चा का विषय रहा है। असल में, इन देशों के अधिकारियों का एक समूह निचले स्तर पर सक्रिय भी हो चुका है। कुछ लोग यह दलील देते हैं कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इन चारों देशों के एक-दूसरे से मेल खाने वाले सामरिक एवं सुरक्षा हित हैं लेकिन कई लोग इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि ऐसे किसी गुट के गठन के लिए जरूरी तालमेल इन देशों के बीच स्थापित हो चुका है।

इस चौकड़ी की संकल्पना सामुद्रिक क्षेत्र में सहयोग से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में उस समय हुई थी जब पूर्व सोवियत संघ के पतन के बाद भारत-अमेरिका के रिश्ते सुधरने शुरू हुए। दोनों देशों के संपर्क को गति देने का काम रक्षा सहयोग ने किया। इसी क्रम में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने 'मालाबार' नाम से संयुक्त अभ्यास करना शुरू किया। समय बीतने के साथ दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग गहरा और मजबूत होता गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि विमानवाहक पोत और पनडुब्बियों की तैनाती भी बिना किसी हिचक के होने लगी। एक दशक पहले जापान को भी इस सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया और फिर ऑस्ट्रेलिया भी इसका अंग बन गया। उस समय पहली बार 'क्वाड' (चौकड़ी) शब्द का इस्तेमाल किया गया।

चीन ने बड़ी नौसैनिक शक्तियों की इस गुटबंदी के खिलाफ एतराज जताया था। यहां तक कि भारत भी इस धारणा को लेकर कुछ संकोच रखता था। इस वजह से कई वर्षों तक 'मालाबार' तीन देशों के नौसैनिक अभ्यास का ही सालाना आयोजन बना रहा। एक साल इसका आयोजन हिंद महासागर की बंगाल की खाड़ी में होता रहा तो अगले साल पूर्वी एशिया के समुद्र में तीनों नौसेनाएं अभ्यास करती रहीं। इसी अवधि में भारत-अमेरिका और भारत-जापान संपर्क में राजनीतिक संपर्क भी तेज हुए। दोनों पक्षों के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों की बैठक (2 प्लस 2) भी हर साल होने लगी।

ऐसे में यह सवाल खड़ा होना लाजिमी है कि इन देशों के इस तरह से एक-दूसरे से जुड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? बाहरी प्रेक्षकों के लिए यह सवाल प्रासंगिक है। आखिर भारत कई अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर रक्षा सहयोग करता है और आसियान जैसे बहुपक्षीय समूहों के साथ के भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। वह दूसरे समूहों ब्रिक्स, आरआईसी और एससीओ का भी हिस्सा रहा है। लेकिन इनमें से किसी भी समूह के सामरिक निहितार्थ भारत-अमेरिका-जापान समूह की तरह नहीं हैं।

भारत और अमेरिका के लिए इस पहलू को हर कोई देख सकता है। अमेरिका के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र प्राथमिक चिंता का विषय रहा है और अगर हिंद महासागर भारत के लिए प्राथमिकता रखता है तो प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मामले भी अहमियत रखते हैं। इसकी वजह यह है कि भारत का आधे से भी अधिक कारोबार समुद्र के इसी रास्ते से होता है और यह बढ़ ही रहा है। दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देश बड़े व्यापारिक साझेदार हैं और अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी-खासी आबादी भी है। भारत के उलट अमेरिका का चीन के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है लेकिन व्यापार के मोर्चे पर दोनों देशों में गहरे मतभेद रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर में चीन का आक्रामक रुख और अमेरिका के बरक्स खुद को महाशक्ति के तौर पर खड़ा करने की उसकी चाहत भी है।

इस स्थिति में भारत और अमेरिका का रक्षा सहयोग में करीबी आना काफी मायने रखता है। आज के समय में अमेरिका भारत को सैन्य साजोसामान आपूर्ति करने के मामले में सबसे आगे है। इस द्विपक्षीय संबंध में कोई कमजोरी नजर नहीं आती है। हालांकि रूस और ईरान को लेकर अमेरिकी नीतियों के चलते उन देशों के साथ हमारे स्वस्थ रिश्ते को कायम रख पाना कभी-कभी मुश्किल भी हो जाता है। हालांकि हालिया घटनाएं बताती हैं कि ये चुनौतियां ऐसी नहीं है कि उनसे पार न पाया जा सके। कुल मिलाकर, दोनों देशों के सामरिक हित काफी स्पष्ट हैं।

अमेरिका का सैन्य सहयोगी और अपने आप में एक बड़ी आर्थिक शक्ति जापान भी इसका हिस्सा बन जाता है। हालांकि भारत और जापान के बीच कारोबार भी बहुत अधिक नहीं हुआ है और न ही इनका रक्षा सहयोग मालाबार अभ्यास से आगे बढ़ पाया है और सैन्य उपकरणों के आदान-प्रदान में भी तब्दील नहीं हुआ है। फिर भी सामरिक मुद्दे इनके रिश्ते को अलग ही श्रेणी में रखते हैं। मसलन, जापान अपनी तेल जरूरतों के लिए खाड़ी देशों से हिंद महासागर के रास्ते होने वाले आयात पर निर्भर है। तेल लाने वाले जहाज चीन के प्रभाव वाले दक्षिण चीन एवं पूर्वी चीन सागर से होकर गुजरते हैं। इस इलाके में जापान अपने हितों की रक्षा अमेरिकी समर्थन से कर सकता है लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए उसे भारत की मदद की जरूरत है।

इसके अलावा भारत की ही तरह जापान का भी चीन के साथ पूर्वी चीन सागर में सीमा विवाद चल रहा है। जापान के साथ कारोबारी रिश्ता परवान चढ़ने के बावजूद चीन उसे एक विरोधी देश के तौर पर ही देखता है। इन दोनों कारणों से जापान के लिए भारत हिंद-प्रशांत मामलों में एक उपयोगी साझेदार बन जाता है। इसके साथ अगर दक्षिणी चीन सागर में भारत के निहित हितों और जापान की अहम सामुद्रिक क्षमता को भी ध्यान में रखें तो दोनों देशों के साझा हित पूरी तरह साफ हो जाते हैं। वैसे जापान की गिनती अब भी अमेरिका जैसे सामरिक साझेदार के तौर पर नहीं की जा सकती है लेकिन उसमें इस त्रिकोणीय संबंध को सशक्त करने की पूरी क्षमता है। ऐसे में इस पूर्वी एशियाई देश को भी अपने साथ रखना वांछनीय है।

इस चौकड़ी का चौथा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया है। हालांकि अभी तो वह केवल औपचारिक तौर पर ही इस समूह का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा कारोबार बहुत अधिक नहीं है। वह चीन का सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश है और उसका चीन के साथ किसी भी तरह का सीमा या अन्य विवाद भी नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का सैन्य सहयोगी देश है लेकिन भारत के नजरिये से देखें तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के हितों में समान बातें बहुत कम हैं। जहां तक निर्बाध समुद्री परिवहन का सवाल है तो वह कारोबार के लिए नौवहन पर निर्भर किसी भी देश का बुनियादी हित होता है।

केवल इतने भर से ऑस्ट्रेलिया के साथ भरोसेमंद सामरिक रिश्ते भारत के लिए अपरिहार्य नहीं हो जाते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर क्षेत्र में एक अहम नौसैनिक ताकत है और उसके साथ संबंध रखना जरूरी है लेकिन उतने भर से वह इस चौकड़ी में बड़ी भूमिका निभाने का हकदार नहीं बन जाता है। लेकिन भारत, अमेरिका और जापान की स्थिति एकदम अलग है। ये देश वर्ष 2030 तक न केवल दुनिया की शीर्ष चार में से तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे बल्कि हरेक भागीदार देश को यह लगता है कि दूसरे देश उसके सामरिक हितों को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। इनमें से हरेक देश के लिए चीन की बढ़ती शक्ति आकांक्षाएं चिंता का विषय हैं।

निस्संदेह, इस गठबंधन को लेकर जाहिर की गई खामियों के आने वाले वर्षों में दूर हो जाने की संभावना है। और इस रिश्ते को आगे संवारने की भी जरूरत होगी। 'क्वाड' गठजोड़ आगे जारी रह सकता है लेकिन एक सामरिक जरूरत के तौर पर अभी इस अवधारणा का वक्त नहीं आया है।

(लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्श बोर्ड के सदस्य रहे हैं)

कोहली-धोनी की सफल जोड़ी में छिपे हैं कॉर्पोरेट नेतृत्व के गुर

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

क्रिकेट टीमों के कप्तान सीमित ओवरों के मैच में नाजुक हालत होने पर अमूमन 30 गज के दायरे के भीतर ही क्षेत्ररक्षण करना पसंद करते हैं। इससे उन्हें बदलते हालात के हिसाब से नियंत्रण रखने और गेंदबाजों एवं नजदीकी क्षेत्ररक्षकों को सलाह देने में आसानी होती है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान इस बंधी-बंधाई लकीर से अलग जा चुके हैं। मैच-दर-मैच वह मुकाबले के अंतिम ओवरों के दौरान सीमारेखा के पास पहुंचे होते हैं। हालांकि इससे भी उन्हें दो फायदे होते हैं। पहला, अपने ताकतवर बाजुओं एवं टांगों का इस्तेमाल करते हुए वह तेजी से गेंद को विकेट की ओर थ्रो कर पाते हैं और दूसरा, इससे टीम के विकेटकीपर को गेंदबाजों को सही लेंथ पर गेंद डालने का सुझाव देने का मौका मिल जाता है। कोहली का तर्क बड़ा सरल है: अगर टीम में महेंद्र सिंह धोनी जैसी काबिलियत एवं विशाल अनुभव रखने वाला विकेटकीपर हो तो उसे स्टंप के पीछे रहते हुए गेंदबाजी के बारे में सबसे अच्छा नजारा मिलता है। वैसे भी मैदान के दूसरे छोर पर खड़ा होने पर भी कोहली और धोनी की आंखें एक-दूसरे के संपर्क में बनी रहती हैं। इस तरह कप्तान को भी विकेट के पास हो रही गतिविधियों के बारे में सबकुछ पता रहता है और बनाई जा रही रणनीति से भी वह परिचित रहता है। धोनी एवं कोहली के बीच के भरोसे, दोस्ती और एक-दूसरे के प्रति सम्मान भाव ने यह मिथक तोड़ने में मदद की है कि एक कप्तान को किसी राजा की तरह बरताव करना चाहिए अन्यथा उसे अपने दायित्व से भागने वाला मान लिया जाएगा।

लेकिन इस प्रचलित धारणा के उलट कोहली-धोनी की जोड़ी नेतृत्व का बेहतरीन नजारा पेश करती है। कोहली अपने क्रियाकलाप से एक बेहद आत्मविश्वासी नेता के तौर पर नजर आते हैं जिसे यह बखूबी पता है कि अपने साथी खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे कराया जाए और टीम का साझा मकसद हासिल करने में योगदान दिया जाए। कोहली ने कई मौकों पर यह साफ किया है कि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन कप्तानों में शुमार किए जाने वाले धोनी के अनुभव का लाभ उठाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आखिर धोनी बेहद मुश्किल हालात में भी अपना संयम बनाए रखने की अनूठी काबिलियत रखते हैं। अपने तमाम साक्षात्कारों में कोहली ने यह माना है कि जब भी उन्हें जरूरत महसूस होती है वह धोनी की सलाह लेते हैं और 10 में से 9 बार उन्हें अपने पूर्व कप्तान से मिली सलाह सही ही साबित होती है। कोहली का मानना है कि टीम में धोनी जैसे अनुभवी खिलाड़ी की मौजूदगी अपने आप में एक वरदान है, खासकर उनकी कप्तानी के शुरुआती दिनों में। धोनी ने भी इसी अंदाज में अपने मौजूदा कप्तान की तारीफ करते हुए कोहली को 'पहले ही महानता का दर्जा' हासिल कर चुका खिलाड़ी बताते हुए कहा है कि वह खुद को चर्चा में आने से बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसके हकदार कप्तान होते हैं। एक नेतृत्वकर्ता के लिए सबसे अहम बिंदु यह है कि अपनी टीम की नजरों में वह विश्वास से ओतप्रोत दिखे। एक नेता के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने का मौका तब होता है जब वह अपने पूर्ववर्ती से बात करता है या बरताव करता है। महान नेताओं को कभी भी अपने से पहले उस पद पर रहे व्यक्ति से सलाह और प्रेरणा लेने में कभी कोई समस्या नहीं होती है। उन्हें कभी भी दूसरे की आलोचना करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वे खुद को लेकर आश्वस्त होते हैं।

सच कहें तो लीजेंड का दर्जा हासिल कर चुके कप्तान या सीईओ से कमान संभालना सामान्य नेतृत्व की तुलना में कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया है। कर्मचारी या खिलाड़ी इस बदलाव के बेमेल होने को लेकर चर्चा करेंगे और पुराने बॉस से नए बॉस की तुलना भी होगी। ऐसे में कोहली को श्रेय जाता है कि अपने प्रदर्शन से रोलमॉडल बन जाने के बावजूद कोहली ने धोनी को वह सम्मान दिया है जिसके वह हकदार हैं।

दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही एक-दूसरे से काफी अलग मिजाज वाले शख्स हैं। जहां कोहली काफी आक्रामक नजर आते हैं वहीं धोनी भारत के सर्वाधिक शांत एवं संयमित कप्तानों में से एक रहे हैं। वैसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ऐसा होना भी चाहिए। कोई बोर्ड नया अगुआ चुनते समय सबसे बड़ी यही गलती कर सकता है कि वह मशहूर सीईओ की नकल ही तलाशने लगे। ऐसा होना तो नामुमकिन ही है। किसी भी सूरत में, एक संगठन के लोग काफी समझदार होते हैं और अगर उन्हें यह लगा कि आप किसी और की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वे आपको धूर्त समझने लगेंगे।

कोहली का सबसे बड़ा नेतृत्व कौशल यह है कि उन्हें अपने पूर्ववर्ती से उनका सर्वश्रेष्ठ निकालने की कला आती है और वह धोनी के विदा होने के पहले उनसे सारी बारीकियां सीख लेना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि इसके लिए उन्हें अपने पूर्व कप्तान की छाया बनने की जरूरत नहीं है।

इस कहानी का सार बहुत सरल है। नेतृत्व को रिश्ते बनाने का तरीका पता होना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि किसी समूह का समेकित आईक्यू किसी भी अकेले व्यक्ति के आईक्यू से वजनदार होगा और चाहे वह कितना भी समझदार हो उसे सबकुछ पता नहीं हो सकता है। जब सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का दायित्व संभाला था तो उन्हें बखूबी मालूम था कि बिल गेट्स के सर्चलाइट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह करना है? गेट्स ने भी कंपनी की तरफ से लाए जाने वाले नए उत्पादों के बारे में विश्लेषणात्मक नजरिया देकर नडेला की चाहत पूरी की। नडेला ने यह भी कहा कि वह कर्मचारियों को उत्साहित करने की गेट्स की खासियत का भी फायदा उठाना चाहते हैं।

आप नडेला की जगह कोहली को रखें और गेट्स के स्थान पर धोनी को रखकर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन क्यों है?

कानाफूसी

हिंदी को प्रोत्साहन

संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सांस्कृतिक प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र ने कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों के लिए नकद इनाम की घोषणा की है। विभाग के प्रभारी निदेशक की ओर से जारी एक आधिकारिक नोट के मुताबिक जो कर्मचारी प्रति दिन कम से कम पांच नोटिंग या प्रति माह 300 नोटिंग या आधिकारिक पत्र हिंदी में लिखेंगे, वे इस पुरस्कार को पाने की पात्रता रखेंगे। नोट में यह भी कहा गया कि इसके अलावा भी अपने रोज के कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल करने वालों को उनके सालाना काम की समीक्षा में भी इसके आधार पर कुछ अतिरिक्त तवज्जो दी जाएगी। ऐसी हर प्रविष्टि को एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा। हालांकि इसमें यह उल्लेख नहीं है कि इन प्रविष्टियों को छांटने और पुरस्कृतों के चयन का काम कैसे किया जाएगा।

गठबंधन की उलझन

लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की अन्य दलों के साथ गठबंधन करने की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन अंतिम चरण में था कि तभी बातचीत नए सिरे से मुसीबत में पड़ गई। कुल 28 सीटों वाले कर्नाटक में कांग्रेस जनता दल को नौ लोकसभा सीट देने को तैयार थी जबकि वह 19 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। परंतु सीटों के चयन को लेकर एक नया झगड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस अपने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व में मैसूरु और तुमकुर सीट छोड़ने की इच्छुक नहीं थी। वहीं जनता दल सेक्युलर का कहना था कि फिलहाल तुमकुर लोकसभा क्षेत्र की चार विधानसभा सीटों पर उसके विधायक हैं जबकि कांग्रेस का केवल एक। रही बात मैसूरु की तो वह देवेगौड़ा परिवार की पारंपरिक सीट है। कांग्रेस 2014 के आम चुनाव में इस सीट पर दूसरे स्थान पर थी जबकि भाजपा को जीत मिली थी।

आपका पक्ष

पेट्रोलियम का रणनीतिक भंडारण

देश की अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। ईंधन के सबसे बड़े स्रोत के रूप में पेट्रोलियम पदार्थों का महत्त्व जगजाहिर है। विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों के अब तक खोजे गए ज्ञात अधिकांश भंडार चुनिंदा क्षेत्रों एवं देशों के पास ही है। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीकी देश, पश्चिम एशिया के देश, अमेरिका, चीन एवं रूस है। विश्व के अन्य अधिकांश देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इन देशों पर ही निर्भर हैं जिसमें भारत भी शामिल है। भारत पेट्रोलियम आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर है। यह निर्भरता कुल मांग का 90 प्रतिशत से अधिक है। आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा आने पर देश में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ जाती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य जहां सर्वत्र तनाव एवं अविश्वास का वातावरण है। ऐसे में किसी भी क्षण पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति में बाधा की

संभावना बढ़ गई है। भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले देशों में ईरान वैश्विक प्रतिबंध झेल रहा है। कई खाड़ी देश राजनीतिक अस्थिरता एवं आईएस जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों से बेहाल हैं। अमेरिका के हमारे संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों की जो हालात है उसे देखते हुए पेट्रोलियम पदार्थों

पेट्रोलियम जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत 90 फीसदी से अधिक आयात करता है

के सामरिक भंडारण का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। युद्ध काल में दुश्मन देश पेट्रोलियम आपूर्ति में बाधा पहुंचाने को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इन परिस्थितियों में अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में ऊर्जा की अबाध आपूर्ति बरकरार रखने के लिए हमें पेट्रोलियम पदार्थों के रणनीतिक तथा सामरिक भंडारण के विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए ठोस कदम उठाने होंगे। विषम परिस्थिति से बचने के लिए ही खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला सऊदी अरब अब तकनीक की मदद से अनाज का उत्पादन कर इसका भंडारण कर रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों के रणनीतिक भंडारण के लिए सरकार द्वारा किए गए अभी तक के प्रयास नाकाफी रहे हैं। यह केवल विचार करने तक सीमित रह गया है। हाल में भारत सरकार ने सऊदी अरब को पेट्रोलियम पदार्थ के रणनीतिक भंडारण में निवेश के लिए आमंत्रित किया है जो अच्छी पहल है।

ऋषभ देव पांडेय, कोरबा

नशे की लत से मिले छुटकारा

देश में युवाओं की आबादी एक तिहाई से अधिक है। अगर इन्हें उचित मार्गदर्शन मिले तो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकते हैं और देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही देश को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन हाल में युवाओं में बढ़ती नशे की लत एक गंभीर समस्या है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 28 करोड़ से अधिक लोग नशे के आदी हैं और 6 करोड़ लोग गंभीर स्थिति में है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश की रीढ़ कहे जाने वाले युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। सरकार द्वारा नशा मुक्ति के क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन और जागरूकता में वृद्धि हुई है। लेकिन व्यक्ति को स्वयं नशे को छोड़ने की जरूरत है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।